

सामाजिक और मानव अधिकार कार्रवाई के लिए प्रावधान

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2012 की सिविल अपील संख्या 2202)

10 मई, 2023

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950: 5 वीं अनुसूची-की शक्ति

राज्यपाल द्वारा जारी अनुसूचित क्षेत्र-आयोजित: सभी केंद्रीय और राज्य के कानून जो पूरे उड़ीसा राज्य पर लागू होते हैं, वे अनुसूचित क्षेत्र पर तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा एक विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है।

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अप्रयोज्य विशेष अधिनियम-पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के तहत माननीय राज्यपाल की शक्ति यह निर्देश देने तक सीमित है कि कोई विशेष कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, यह ऐसे संशोधनों के साथ लागू होगा जो हो सकता है

पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट या विनियम बनाते समय पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 का उपखंड (2)-पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के तहत राज्यपाल की शक्ति मौलिक अधिकारों का स्थान नहीं लेती है।

कला का खंड (ई)। 19 (1) नागरिकों पर अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी प्रयोग किया जा सकता है।

कला. 19 (1) (ई)-रहने का अधिकार-यदि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में बसने का अधिकार है-आयोजित: के उपखंड (ई) के तहत

कला का खंड (1)। 19 , प्रत्येक नागरिक को भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है-हालाँकि, एक कानून बनाकर,

उक्त मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यह मानते हुए भी कि पांचवीं अनुसूची एक कानून है, यह कला के तहत मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कोई बाधा नहीं डालती है। 19 (1) - अतः यह नहीं कहा जा सकता कि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में बसने का कोई अधिकार नहीं है।

372 सामाजिक और मानव अधिकार अधिनियम के लिए प्रावधान V.

भारत और ओआरएस का संघ।

कलाएँ। 330 और 332-लोकसभा और राज्य विधानमंडल

अनुसूचित जनजाति-इसके अलावा, 2002 का अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है। अनुसूचित क्षेत्र इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में परमादेश जारी करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है।

परिसीमन अधिनियम, 2002।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: वोट देने का अधिकार-अनुसूचित क्षेत्र में गैर-जनजातीय लोगों को वोट देने का अधिकार: 1950 अधिनियम है

अनुसूचित क्षेत्र पर लागू-मतदान का अधिकार 1950 के अधिनियम के भाग III द्वारा शासित होगा-प्रत्येक पात्र मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है-इस प्रकार, मतदान करने का पात्र कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा है, उसे मतदान करने का अधिकार है, भले ही वह एक गैर-जनजातीय हो-यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल एक व्यक्ति जिसका संबंध अनुसूचित क्षेत्र से हो।

अनुसूचित क्षेत्र के लोग अनुसूचित क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) को सीधे पढ़ने पर, भारत के संविधान की शक्ति -

उक्त उपखंड (1) के तहत माननीय राज्यपाल का विस्तार एक अधिसूचना द्वारा निर्देश देने तक है कि कोई विशेष केंद्रीय या राज्य

कानून राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, और एक अधिसूचना द्वारा निर्देश दिया जाएगा कि कोई विशेष राज्य या केंद्रीय अधिनियम कुछ संशोधनों के अधीन किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा। उपखंड (1) का पहला भाग इस आधार पर आगे बढ़ता है कि किसी राज्य पर लागू होने वाले सभी राज्य और केंद्रीय विधान हैं: उक्त राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू। अन्यथा, माननीय राज्यपाल को यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान करने का कोई कारण नहीं था कि विशेष विधान किसी विशेष अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। [पैरा 8] [379-डी-जी]

1.2 अपीलार्थी द्वारा उठाया गया तर्क कि जब तक कि आवेदन करने वाले माननीय राज्यपाल द्वारा कोई विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है

किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए केंद्रीय या राज्य के कानून, उक्त कानून [2023] 5 एस. सी. आर. नहीं होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अनुसूचित क्षेत्र पर आवेदन करना, कम से कम कहने के लिए, बेतुका है।

[पैरा 11] [381-सी-डी]

1.3 सभी केंद्रीय और राज्य कानून जो पूरे उड़ीसा राज्य पर लागू होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र पर तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राज्यपाल द्वारा एक विशिष्ट अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें किसी विशेष अधिनियम को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू नहीं किया जाता है। पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के तहत माननीय राज्यपाल की शक्ति यह निर्देश देने तक सीमित है कि कोई विशेष कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, यह ऐसे संशोधनों के साथ लागू होगा जो पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में या पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (2) के संदर्भ में विनियम बनाते समय निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के तहत माननीय राज्यपाल की शक्ति का स्थान नहीं लेता है -

भारत के संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के उपखंड (ई) द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपयोग अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी किया जा सकता है। [पैरा 13] [385-सी-जी]

1.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ई) के तहत, प्रत्येक नागरिक को रहने और बसने का अधिकार है

भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग में। हालाँकि, एक कानून बनाकर, अनुच्छेद 19 के खंड (5) में दिए गए उक्त मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए, इस दलील को खारिज कर दिया जाता है कि गैर-आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में बसने का कोई अधिकार नहीं है। यह दलील कि पाँचवीं अनुसूची संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, गलत धारणा है। यह मानते हुए भी कि पाँचवीं अनुसूची एक कानून है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कोई बाधा नहीं डालती है। [पैरा 14,15] [385-जी-एच; 386-ए-बी]

1.5 जहाँ तक मतदान के अधिकार का संबंध है, 1950 का अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है और इसलिए, अपीलार्थी

यह तर्क नहीं दे सकते कि केवल अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में मतदान कर सकता है। मतदान का अधिकार 1950 के अधिनियम के भाग III द्वारा शासित होगा। प्रत्येक पात्र मतदाता एडीवैसिस फॉर सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्ट V में पंजीकृत होने का हकदार है।

भारत और ओआरएस का संघ।

एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है। इसलिए, वोट देने के योग्य कोई भी व्यक्ति जो सामान्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र में रहता है, उसे वोट देने का अधिकार है, भले ही वह गैर-जनजातीय हो। [पैरा 16] [386-बी-डी]

1.6 सभी लोकसभाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के संबंध में

और किसी अनुसूचित क्षेत्र में राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्रों में, अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि किसी अनुसूचित क्षेत्र के सभी निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के संदर्भ में आरक्षण की आवश्यकता है। इन प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्रों के सभी निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा, 2002 का अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है। इसलिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में अनिवार्य लिखित आदेश जारी करने की उक्त प्रार्थना को भी खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 17] [386-डी-ई]

1.7 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को लागू किया गया था -

जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरा भारत। पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) के तहत माननीय राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग के अभाव में, उक्त कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू था। [पैरा 18] [386-ई-एफ]

1.8 अपील में बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है, और उच्च

अदालत सही थी जब उसने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। [पैरा 19] [386-जी]

चेन्नोलु लीला प्रसाद राव और अन्य। वी. आंध्र राज्य

प्रदेश और अन्य (2021) 11 एस. सी. सी. 401-इसके बाद।

रामगढ़ के राजा बहादुर कामाक्ष्या नारायण सिंह

वी. आयकर आयुक्त बिहार (1947) संघीय

न्यायालय की रिपोर्ट 130; चट्टूराम बनाम। के आयुक्त

आयकर ए. आई. आर. 1947 एफ. सी. 32-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

(2021) 11 एस. सी. सी. 401

पैरा 11

पीछा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2202

2012 से।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. पी. मोहंती, डी. के. सिंह, राम नारायण मोहंती, दिनेश एस. बदियार, समींद्र कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सिबो शंकर मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, सुश्री अपूर्व शर्मा, सुनील मुंग, श्रीमती अनिल कटियार, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपूर्णा सिंह, सुश्री साक्षी उपाध्याय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

वास्तविक पहलू

1. 31 दिसंबर, 1977 को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड 6 के उपखंड (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उड़ीसा राज्य में सुंदरगढ़ के पूरे जिले को अनुसूचित क्षेत्र (संक्षेप में, 'अनुसूचित क्षेत्र') घोषित किया। अपीलार्थी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी,

1860, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया गया। रिट याचिका में पहला तर्क यह था कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छोड़कर, किसी को भी बसने का अधिकार नहीं है। रिट याचिका में यह तर्क दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है और अनुसूचित क्षेत्र में रहता है, एक गैरकानूनी निवासी है और इसलिए, अनुसूचित क्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से वंचित है। आगे यह तर्क उठाया गया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अलावा किसी भी उम्मीदवार को अनुसूचित क्षेत्र में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

2. याचिका में उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) को देखते हुए जब तक कि कोई विशिष्ट प्रावधान न हो। राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना

किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष रूप से केंद्रीय या राज्य कानून, केंद्रीय या राज्य कानूनों का कोई भी प्रावधान उस विशेष अनुसूचित क्षेत्र के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (संक्षेप में, '1950 अधिनियम') और परिसीमन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, '2002 अधिनियम') सामाजिक और मानव अधिकार अधिनियम V के अधीन अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

ऐसी किसी भी अधिसूचना का अभाव। उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने विवादित फैसले से रिट याचिका को खारिज कर दिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील को इस न्यायालय द्वारा 14 फरवरी 2012 के आदेश के अनुसार अनुमति देने के अनुसार प्राथमिकता दी गई है।

प्रस्तुतियाँ

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है। स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि किसी विशेष अधिनियम को किसी विशेष अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करने की आवश्यकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्र में कानून को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक माननीय राज्यपाल द्वारा संसद और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक अधिनियम के शीर्षक और अन्य विवरणों को स्पष्ट रूप से शामिल करते हुए एक विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, जो अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगी, तब तक संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ई) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रचलित है वह पांचवीं अनुसूची के खंड 5 के अनुसार बनाया गया कानून है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रामगढ़ बनाम। आयकर आयुक्त बिहार 1 और चट्टूराम बनाम के मामले में। आय कर आयुक्त 2 के समर्थन में पाँचवें के खंड 5 के उपखंड (1) की उनके द्वारा की गई व्याख्या

अनुसूची. मामले के बयान में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को माननीय राज्यपाल द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए उक्त कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। हमने उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है।

हमारा दृष्टिकोण

7. इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या केंद्रीय और राज्य अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू हो सकते हैं जब तक कि - उक्त अधिनियमों को अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करने वाली विशिष्ट अधिसूचना माननीय राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। पाँचवीं अनुसूची का खंड 5 इस प्रकार है:

" 5. अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानून। - (1) इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू होगा, जो ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन होगा जो वह अधिसूचना और इस उप-संविधान के तहत दिए गए किसी निर्देश में निर्दिष्ट करे।

विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे विनियम (क) सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करना।

ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना;

1 (1947) संघीय न्यायालय ने 130 2 ए. आई. आर. 1947 एफ. सी. 32 सामाजिक और मानव अधिकार अधिनियम के लिए प्रावधान की रिपोर्ट दी।

भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

(ग) व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रूप में व्यवसाय के संचालन को विनियमित करना।
जो अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऐसे क्षेत्रों में धन उधार देते हैं

क्षेत्र।

(3) उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट कोई भी विनियमन बनाने में

(2) इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर
सकता है। संसद या राज्य के
विधानमंडल या किसी भी मौजूदा

कानून जो अभी के लिए विचाराधीन क्षेत्र पर लागू है।

(4) इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए सभी विनियम प्रस्तुत किए जाएंगे।

कोई प्रभाव नहीं।

(5) इस अनुच्छेद के तहत कोई विनियमन नहीं बनाया जाएगा जब तक कि

विनियमन बनाने वाले राज्यपाल के पास, उस मामले में जहां एक है
राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद ने ऐसी परिषद से परामर्श किया।

(जोर

दिया गया)

8. पाँचवें के खंड 5 के उपखंड (1) के सादे पठन पर

अनुसूची, उक्त उपखंड (1) के तहत माननीय राज्यपाल की शक्ति निम्नलिखित तक फैली हुई है:

एक अधिसूचना द्वारा निर्देश देना कि एक विशेष केंद्रीय या राज्य

आई.

और;

एक अधिसूचना द्वारा निर्देश देते हुए कि एक विशेष राज्य या केंद्रीय

ii.

अधिनियम एक अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा, बशर्ते कि कुछ
संशोधन।

उपखंड (1) का पहला भाग इस आधार पर आगे बढ़ता है कि सभी

किसी राज्य पर लागू होने वाले राज्य और केंद्रीय कानून उक्त राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते
हैं। अन्यथा, कोई कारण नहीं था

माननीय राज्यपाल को यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान करना कि वह विशेष विधान किसी विशेष अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा।

9. खंड 5 की व्याख्या करने के लिए, विद्वान वकील

अपीलार्थी ने राजा बहादुर और छत्रम 2 के मामलों में संघीय न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। दोनों निर्णय भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 से संबंधित हैं, जो इस प्रकार है:

" बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों का प्रशासन

क्षेत्र:

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

92. (1) एक प्रांत का कार्यकारी अधिकार बहिष्कृत तक फैला हुआ है।

और उसमें आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, लेकिन, इसके बावजूद इस अधिनियम में कुछ भी, संघीय विधानमंडल का कोई अधिनियम या

प्रांतीय विधानमंडल, एक बहिष्कृत क्षेत्र पर लागू होगा

या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, जब तक कि राज्यपाल जनता द्वारा

अधिसूचना इस प्रकार निर्देश देती है, और राज्यपाल ऐसा देने में

किसी अधिनियम के संबंध में निर्देश यह निर्देश दे सकता है कि अधिनियम

क्षेत्र में या किसी निर्दिष्ट भाग में इसके अनुप्रयोग में

इसके, ऐसे अपवादों के अधीन प्रभाव पड़ता है या

परिवर्तन जैसा वह उचित समझता है।

(2) राज्यपाल शांति और भलाई के लिए नियम बना सकता है। प्रांत के किसी भी क्षेत्र की सरकार जो अभी के लिए है

यह कुछ समय के लिए विचाराधीन क्षेत्र पर लागू है। इस उप-धारा के तहत बनाए गए विनियम प्रस्तुत किए जाएंगे।

गवर्नर-जनरल को तुरंत और जब तक उनके द्वारा सहमति नहीं दी जाती उसके विवेकाधिकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इस भाग के प्रावधान

महामहिम की अनुमति न देने की शक्ति के संबंध में इस अधिनियम का अधिनियम ऐसे किसी भी विनियम के संबंध में लागू होंगे जिन्हें

प्रांतीय विधानमंडल ने उनके द्वारा सहमति दी।

(3) राज्यपाल, किसी प्रांत के किसी भी क्षेत्र के संबंध में,

कुछ समय के लिए, एक बहिष्कृत क्षेत्र, अपने कार्यों का प्रयोग करता है

उसका विवेक "।

(जोर

दिया गया)

10. अनुच्छेद 395 के आधार पर, भारत सरकार अधिनियम, 1935

निरस्त कर दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 की उप-धारा (1) और पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 का उप-खंड (1) पूरी तरह से अलग हैं। धारा 92 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि संघीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल का कोई भी अधिनियम किसी बहिष्कृत क्षेत्र पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश न दे। तथापि, पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 का उपखंड (1) माननीय राज्यपाल को यह निर्देश देने के लिए अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कि कोई विशेष अधिनियम, राज्य या केंद्र, किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। उनके पास यह निर्देश देने की भी शक्ति है कि एक विशेष अधिनियम सामाजिक और मानव अधिकार अधिनियम V के लिए सहायक होगा।

भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

राज्यपाल उस आशय का एक विशिष्ट निर्देश जारी कर रहे हैं। इस प्रकार, निर्भरता भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 की उप-धारा (1) पर रखा गया है जो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है।

11. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब तक केंद्र या राज्य सरकार को लागू करने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा कोई विशिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की जाती है।

किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए राज्य के कानून, उक्त कानून उक्त अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, कम से कम कहने के लिए, बेतुके हैं। वास्तव में, मुद्दा अब रेज़ इंटीग्रा नहीं है। चेंब्रो लु लीला प्रसाद राव और अन्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का एक बाध्यकारी निर्णय है। वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 3. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 2 में, संविधान पीठ ने ऐसे प्रश्न तैयार किए जिनकी आवश्यकता थी

विचार करें। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 2 इस प्रकार है:

" 2. दिनांकित 11-1-2016 [चेंब्रो लु लीला प्रसाद राव बनाम] आदेश में कई प्रश्नों को विचार के लिए भेजा गया है। ए. पी. राज्य, (2021) 11 एस. सी. सी. 526] हमने परस्पर संबंध के आधार पर प्रश्नों 1 (ए), (बी), (सी) और (डी) को पुनः क्रमांकित किया है। सवाल इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित है: (चेंब्रो लु लीला प्रसाद राव मामला [चेंब्रो लु लीला] प्रसाद राव बनाम। ए. पी. राज्य, (2021) 11 एस. सी. सी. 526], एस. सी. सी. पी. 527 ,

पैरा 1)

(1) भारत के संविधान के पैरा 5 (1), अनुसूची V का दायरा क्या है?

(क) क्या यह प्रावधान राज्यपाल को नया कानून बनाने का अधिकार देता है?

(ख) क्या शक्ति अधीनस्थ विधान तक फैली हुई है?

(ग) क्या उसमें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर हावी हो सकता है?

(घ) क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 371-डी के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के किसी भी समानांतर प्रयोग पर हावी है?

3 3 (2021) 11 एस. सी. सी. 401 [2023] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

- (2) क्या संविधान के तहत 100% आरक्षण की अनुमति है? (3) क्या अधिसूचना केवल अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण पर विचार करती है और अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण पर नहीं?
- (4) क्या अधिसूचना में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तें (यानी मूल और कट-ऑफ तिथि) उचित हैं?

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 39.1 में संविधान पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“ 39.

39.1 . अनुसूची 5 का पैरा 5 (1) राज्यपाल को कोई कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह निर्देश देता है कि -

संसद या राज्य विधानमंडल किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा या अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के साथ लागू होगा। राज्यपाल संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 5 (1) में निहित प्रावधानों के तहत एक नया अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। राज्यपाल के लिए आरक्षित क्षेत्र

पैरा 5 (1) के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। वह इसके दायरे से परे काम नहीं कर सकता है और उसे चारों के भीतर शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है।

प्रावधानों के कोने।

99

39.2
.....

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 40 में, संविधान पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 40. संसद का अधिनियम या उपयुक्त विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। राज्यपाल के पास अधिसूचना द्वारा उनके संचालन को बाहर करने की शक्ति है। में इसकी अनुपस्थिति में, विधानमंडल के अधिनियमों का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में होगा। जतिंद्र बनाम। बिहार प्रांत [जतिंद्र बनाम। बिहार प्रांत, 1949 एस. सी. सी. ऑनलाइन एफ. सी. 23: आई. एल. आर. (1949) 28 पैट 703: 1949 एफ. एल. जे. 225], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पैरा 5 के तहत राज्यपाल की शक्ति एक विधायी शक्ति है और राज्यपाल को अधिनियम या धारा के प्रावधानों को बदलने या संशोधित करने का अधिकार है जैसा कि वह अधिसूचना जारी करके उचित समझता है। पैरा 5 (1) के तहत शक्ति सामाजिक और मानव अधिकार अधिनियम V के लिए विभाजन के राज्यपाल के निर्णय को लागू करने तक सीमित है।

भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

एक अधिनियम लागू करें या संशोधन करें या अपवाद बनाएँ।
है, लेकिन यह सीमित है

यद्यपि शक्ति कुछ हद तक विधायी

संसद या राज्य के अधिनियम के संबंध में प्रयोज्यता, संशोधन या अपवाद पैदा करना। जबकि पैरा 5 (2) स्वतंत्र विधान की शक्ति प्रदान करता है, राज्यपाल के पास पूर्ण शक्ति है -

शांति और सुशासन के लिए नियम बनाना

अनुसूचित क्षेत्र। आवश्यकता के बारे में निर्णय लेने के लिए वह विश्वास का भंडार है। राज्यपाल को पैरा 5 (3) द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम को अनुसूची 5 के पैरा 5 (2) के तहत विनियमन बनाने के लिए उसमें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार है। बिहार राज्य [राम कृपाल भगत बनाम। बिहार राज्य, (1969) 3 एससीसी 471 1970 एससीसी

(क्रि) 154] इस प्रकार: (एससीसी पीपी। 478-80 , पैरा 21-23)

" 21. दूसरा प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या 1951 का बिहार विनियमन । राज्यपाल की शक्तियों से अधिक है। विवाद इस प्रकार थे: पहला, कि 1951 का विनियम । बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता था; दूसरा, कि विनियम विषय-वस्तु से संबंधित हैं और इसका मतलब कानून को लागू करने की शक्ति नहीं है और तीसरा, किसी अन्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून का विस्तार करने की शक्ति को विधायी कार्य नहीं कहा गया था, बल्कि एक सशर्त विधानमंडल था। वर्तमान मामले में यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में है। अनुसूचित क्षेत्रों से संविधान के अनुच्छेद 244 और संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा निपटा जाता है। संविधान से पहले, बहिष्कृत क्षेत्रों से भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 91 और 92 द्वारा निपटा जाता था। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र धारा 91 और धारा 92 के तहत परिषद के आदेश द्वारा घोषित क्षेत्र थे। संघीय विधानमंडल या का कोई अधिनियम नहीं प्रांतीय विधानमंडल को किसी बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र पर तब तक लागू होना था जब तक कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश न दे। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 की उप-धारा (2) ने राज्यपाल को किसी ऐसे प्रांत के किसी भी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की जो एक बहिष्कृत या आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र था और इस तरह बनाए गए कोई भी विनियम संघीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल के किसी भी अधिनियम या किसी भी मौजूदा भारतीय कानून को निरस्त या संशोधित कर सकते हैं जो उस क्षेत्र पर [2023] 5 एस. सी. आर. में लागू था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सवाल करते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्ति का विस्तार

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 92 के तहत

गवर्नर को लॉर्ड हैल्सबरी के शब्दों में सम्मानित किया गया
का अधिकतम विवेकाधिकार

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिनियम

इंगित किया "। (रील वी. देखें। आर. [रील बनाम। आर., (1885) एलआर 10 एसी 675

(पीसी)], एसी पी। 678.) उस मामले में जो शब्द गिर गए

न्यायिक समिति द्वारा विचार करने की शक्ति थी

कनाडा की संसद के लिए प्रावधान करने के लिए

प्रशासन, शांति, व्यवस्था और किसी भी देश की अच्छी सरकार

वह क्षेत्र जो अभी किसी भी प्रांत में शामिल नहीं है। यह.
कानून प्रावधानों से अलग है

यह तर्क दिया गया था कि यदि कोई

जो इंग्लैंड में प्रशासन, शांति के लिए बनाया गया था,

व्यवस्था और अच्छी सरकार तब बनी नहीं रह सकती थी

वैध के रूप में। यह दलील स्वीकार नहीं की गई। ये शब्द थे
शक्ति को गले लगाने के लिए आयोजित

शांति के लिए कानून बनाने की व्यापक

और विचाराधीन क्षेत्र के लिए अच्छी सरकार "। "

(जोर दिया गया)

एक बार फिर अनुच्छेद 52 में संविधान पीठ ने सवाल का जवाब दिया

0 निम्नानुसार:

" 52. हमारी राय है कि राज्यपाल की शक्ति

स्पष्ट भाषा को देखते हुए नया कानून उपलब्ध नहीं है

अपवाद या संशोधनों के साथ। इस प्रकार, अधिसूचना अल्ट्रा है।
पैरा 5 (1) पर लागू होता है।

यह संविधान की अनुसूची V के

(जोर दिया गया)

12. पैराग्राफ 80 में संविधान पीठ ने सवाल का जवाब दिया

0. पैराग्राफ 80 इस प्रकार है:

संविधान। राज्यपाल की शक्ति इसके साथ समान है - संसद और राज्य की विधायी शक्ति।
विधायी शक्ति

प्रावधानों के अधीन संसद या राज्य द्वारा प्रयोग किया जा सकता है

संविधान के भाग III का। हमारी सुविचारित राय में,

राज्यपाल की शक्ति सामाजिक और मानव अधिकार अधिनियम V के लिए मौलिक विभाजन का स्थान नहीं लेती है।

भारत और ओआरएस का संघ। [अभय एस. ओकेए, जे.]

संविधान के भाग III के तहत अधिकार। होना ही चाहिए।

भाग III और अन्य प्रावधानों के अधीन प्रयोग किया गया

संविधान। जब पाँचवीं अनुसूची का पैरा 5 शक्ति प्रदान करता है

राज्यपाल पर, यह मनमाने ढंग से शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं है।

संवैधानिक प्राधिकरणों। इनका प्रयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए। संविधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। द.

शक्तियाँ अवमूल्यन में नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ाने में हैं

संवैधानिक उद्देश्य और उद्देश्य।

(जोर दिया गया)

13. इसलिए, निष्कर्ष निकालने के लिए;

केंद्र और राज्य के सभी कानून जो इन पर लागू होते हैं -

((i)

पूरा उड़ीसा राज्य इस पर लागू होता रहेगा

अनुसूचित क्षेत्र जब तक कि उप के तहत शक्तियों का प्रयोग न किया जाए

पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 का खंड (1) है -
माननीय राज्यपाल द्वारा जारी विशिष्ट अधिसूचना

एक विशेष अधिनियम जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से लागू नहीं होता है;

के खंड 5 के तहत माननीय राज्यपाल की शक्ति

((ख)

पाँचवीं अनुसूची यह निर्देश देने तक सीमित है कि कोई विशेष कानून

अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या इसके साथ लागू होगा

अनुसूची या उपखंड के संदर्भ में विनियम बनाते समय
(2) पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 का;

((ग) संविधान के खंड 5 के अधीन माननीय राज्यपाल की शक्ति

पाँचवीं अनुसूची मौलिक अधिकारों का स्थान नहीं लेती है।

भारत के संविधान के भाग III के तहत; और

((iv) इसलिए, उपखंड द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार

(ई) नागरिकों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) का

अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में भी प्रयोग किया जा सकता है।

14. संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ई) के तहत

भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार है। हालांकि, एक कानून बनाकर, उचित

सी. टी. एन. एस. को उक्त मौलिक अधिकार पर रखा जा सकता है जैसा कि प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 19 की धारा (5)। इसलिए हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि उन्हें अनुसूचित क्षेत्र में बसने का कोई अधिकार नहीं है।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. यह तर्क कि पाँचवीं अनुसूची द्वारा बनाई गई एक विधि है

संसद को गलत समझा गया है। यह मानते हुए भी कि पाँचवीं अनुसूची एक कानून है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर कोई बाधा नहीं डालती है।

16. अब, हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्या एक गैर-आदिवासी को अनुसूचित क्षेत्र में मतदान करने का अधिकार है। जहाँ तक मतदान का अधिकार है

संबंधित, 1950 का अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है और इसलिए, अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता है कि केवल अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों में मतदान कर सकता है। मतदान का अधिकार 1950 के अधिनियम के भाग III द्वारा शासित होगा। प्रत्येक पात्र मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति वोट देने के योग्य जो आम तौर पर अनुसूचित क्षेत्र में रहता है, उसे वोट देने का अधिकार है, भले ही वह एक गैर-आदिवासी हो।

17. जहाँ तक अनुसूचित क्षेत्र में सभी लोकसभा और राज्य विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने का संबंध है, अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता है कि अनुसूचित क्षेत्र के सभी निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के संदर्भ में आरक्षण की आवश्यकता है। इन प्रावधानों में यह प्रावधान नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्रों के सभी निर्वाचन क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्र आरक्षित होंगे। इसके अलावा, 2002 का अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होता है। इसलिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में अनिवार्य लिखित आदेश जारी करने की उक्त प्रार्थना भी खारिज की जानी चाहिए।

18. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था। पाँचवीं अनुसूची के खंड 5 के उपखंड (1) के तहत माननीय राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग के अभाव में, उक्त कानून अनुसूचित क्षेत्र पर लागू था।

19. इसलिए हमारा मानना है कि अपील में कोई दम नहीं है और जब उच्च न्यायालय ने रिट को खारिज कर दिया तो वह सही था।

अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका। केवल इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, हम अपीलार्थी को लागत से भारित करने से बचाते हैं।

20. इसलिए, अपील को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन (सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)